

मुकदमों का विवरण

शिवमणि और एएनआर।

बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व, वेल्लोर टॉक पुलिस स्टेशन, वेल्लोर जिला

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 3619) नवंबर 28, 2023

[विक्रम नाथ और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: पीड़ितों को मामूली चोटें आईं। क्या नीचे दिए गए न्यायालयों को अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में न्यायसंगत ठहराया गया था। 307 भारतीय दंड संहिता .

दंड संहिता, **1860-एस. एस. 323, 324 और 307-विचारण विचारण न्यायालय** ने अपीलार्थियों (**अभियुक्त Nos. 3 और 4**) यू/एस को दोषी ठहराया। **307**, भारतीय दंड संहिता **सी. और 10** साल के कठोर कारावास की सजा-उच्च न्यायालय ने कारावास को **10** साल से घटाकर **5** साल कर दिया-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: पीडब्लू-1 और अभियुक्त नं. 1 उनके घरों के बीच एक लेन के बारे में विवाद था-उसी के बारे में एक दीवानी मामला भी उनके बीच लंबित था-आरोपी एन. ओ. एस। 1, 2 और 5 अपीलकर्ताओं (आरोपी Nos. 3 और 4) के साथ पीडब्लू-1 की दुकान पर पहुंचे-आरोपी नंबर 2 के बारे में कहा जाता है कि उसने पीडब्लू-1 के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे पीटा-अपीलकर्ताओं (आरोपी <ID1 और 4) ने पीडब्लू-1 पर चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पीडब्लू-1 उनके हमले से बच गया और अपीलकर्ताओं के हाथों को पकड़ लिया, जिसके परिणामस्वरूप, उसके दाहिने कंधे और बाएं अंगूठे पर घर्षण की चोटें आईं-पीडब्लू-2 (पीडब्लू-1 की मां) भी घायल हो गई-पीडब्लू-13 (डॉक्टर) ने पाया कि चोटें सरल प्रकृति की थीं-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। 323 और भारतीय दंड संहिता **सी. की धारा 324** बनाई जा सकती है-इस प्रकार, यू/एस के तहत दोषसिद्धि। 307, भारतीय दंड संहिता **सी. अस्थिर है।**

849

[पैरा 5, 6, 9, 10, 11] 850 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम, (2005) 5 एससीसी 554:[2005] 1 पूरका एस. सी. आर. 562; जाग राम बनाम हरियाणा राज्य, (2015) 11 एस. सी. सी. 366:[2015]

11 एससीआर 1004; मध्य प्रदेश राज्य बनाम कान्हा, (2019) 3 एससीसी 605: [2019]

1 एस. सी. आर. 1074-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता :2023 की आपराधिक अपील No.3619।

2015 के सी. आर. एल. ए. No.228 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 06.08.2021 से।

रूप:

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. पार्थिवन, सुश्री प्रियरंजनी नागमुथु, आर. सुधाकरन, जी. आर. विकास, बिलाल मंसूर, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री शुभी भारद्वाज, सुश्री वैदेही रस्तोगी, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे।

1. पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी। 2. छुट्टी दे दी गई।

3. वर्तमान अपील 2015 की आपराधिक अपील में मद्रास में उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश और निर्णय (जिसे इसके बाद "विवादित निर्णय" के रूप में संदर्भित किया गया है) (जिसे इसके बाद "उच्च विचारण न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ताओं के नेतृत्व में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307 (जिसे इसके बाद "आई. पी. सी." के रूप में संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और प्रत्येक को "आई. डी. 2" के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील की गई है, लेकिन 10 साल के कठोर कारावास की सजा को घटाकर 5 साल कर दिया गया है।

851

शिवमणि बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि, वेल्लोर टॉक पुलिस स्टेशन, वेल्लोर जिला [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 852

वास्तविक प्रिज्म:

4. अपीलार्थियों को तीन अन्य लोगों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 (बी), 323, 324, 452 और 307 के साथ 109 के अंतर्गत शिकायतकर्ता की मौत की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए नामित किया गया था। मुकदमे के बाद, अभियुक्त Nos. 1, 2 और 5 को बरी कर दिया गया और अपीलार्थी, जो अभियुक्त Nos. 3 और 4 थे, उन्हें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत दोषी

ठहराया गया और प्रत्येक को 10 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को Rs.1000 की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा की गई अपील पूरी तरह से सफल नहीं हुई और इसके परिणामस्वरूप कठोर कारावास की सजा को 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। यह वर्तमान अपील को जन्म देता है।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुतियाँ:

5. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शिकायतकर्ता-प्रकाश उर्फ चित्रराज/पीडब्लू1 और अभियुक्त संख्या 1 के बीच पूर्व शत्रुता थी। उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का विवरण इस प्रकार दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि पीडब्लू1 और आरोपी नंबर 1 के बीच उनके घरों के बीच एक लेन को लेकर विवाद था। इस संबंध में उनके बीच एक दीवानी मामला भी लंबित था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, न्यायालय के माध्यम से एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया था, जिसने विवादित भूमि को मापा और अभियुक्त संख्या 1 और पीडब्लू1 को भाग आवंटित किए। पीडब्लू1 ने उसे आवंटित हिस्से के भीतर बाड़ लगा दी थी और इस वजह से आरोपी नंबर 1 उसके साथ झगड़ा करता था। घटना से पंद्रह दिन पहले, आरोपी नंबर 1 ने बाड़ हटा दी थी और फिर से पीडब्लू1 के साथ झगड़ा किया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अनुसार, आरोपी नंबर 1 ने पीडब्लू1 के जीवन को समाप्त करने के लिए आरोपी Nos.2,3,4 और 5 के साथ साजिश रची। नतीजतन, 15.09.2012 पर, जब पीडब्लू1 अपनी किराने की दुकान में था, आरोपी नंबर 1 के उकसावे पर, आरोपी Nos.2 और 5 अपीलार्थियों (आरोपी Nos.3 और 4) के साथ दुकान पर पहुंचे। आरोपी नंबर 2 के बारे में कहा जाता है कि उसने पी. डब्ल्यू. 1 को अभद्र और अश्लील भाषा में गाली दी और हाथ से उसके गाल पर बलपूर्वक पीटा। अपीलार्थियों ने पी. डब्ल्यू. 1 पर चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पी. डब्ल्यू. 1 उनके हमले से बच गया और अपीलार्थियों के हाथ पकड़ लिए, जिसके परिणामस्वरूप उनके दाहिने कंधे और बाएं अंगूठे पर घर्षण की चोटें आईं। यह अलार्म सुनकर पीडब्लू2-इंदिरानी (पीडब्लू1 की मां) उसके बचाव में आई और उस समय आरोपी नंबर 5 ने उसकी पीठ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल से हमला कर दिया, जिससे उसे मामूली चोट लगी। इस बीच, पड़ोसी आ गए

/

[2023] 14 एस सी आर।

घटना स्थल और पीडब्लू1 को बचाने की कोशिश की और उन्हें देखकर आरोपी Nos.2 और 5 ऑटो-रिक्शा में भाग गए। अपीलार्थियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उन्हें एक स्ट्रीटलैम्प चौकी से बांध दिया गया। इसके बाद, उन्हें ग्रामीणों द्वारा प्रतिवादी-पुलिस के सामने पेश किया गया।

6. हालाँकि, यह बताया गया कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप कमोबेश समान प्रकृति के होने के कारण, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि डॉक्टर (पी. डब्ल्यू. 13) ने खुद पाया कि चोटें सरल प्रकृति की थीं और शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर नहीं थीं। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि मारने का कोई इरादा नहीं था; न तो बार-बार प्रहार किए गए थे, न ही यह पूर्व-नियोजित था, जब स्वीकार किया जाता है कि आरोपी नंबर 1 और पीडब्लू 1 के बीच एक दीवानी मुकदमा लंबित था। यह प्रस्तुत किया गया था कि अभियोजन पक्ष की कहानी से भी संकेत मिलता है कि आरोपी नंबर 1 और पीडब्लू 1 के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके कारण पीडब्लू 1 द्वारा पुलिस में शिकायत की गई थी, जिससे दुश्मनी और बढ़ गई। अपीलकर्ताओं पर आरोप है कि वे शिकायतकर्ता की दुकान पर आए थे, जब वह अकेला था, एक-एक चाकू के साथ और शिकायतकर्ता की गर्दन पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वह बाल-बाल बच गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि अपीलकर्ता पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 दोनों को मारने के उद्देश्य से आते और चाकू से लैस होते, तो वे आसानी से शिकायतकर्ता की मृत्यु सुनिश्चित कर सकते थे। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, अपीलार्थियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 324 के अंतर्गत आगे बढ़ने के लिए कुछ औचित्य हो सकता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत नहीं, जैसा कि किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि दोनों पीड़ितों को केवल साधारण चोटें आई थीं, जबकि एक पीड़ित-पीडब्लू 2 ने शिकायत की थी कि वह अपनी पीठ पर हमला होने पर गिर गई थी, लेकिन उसे कोई असाधारण चोट नहीं लगी और वह भी साधारण प्रकृति की पाई गई। इसी तरह, दूसरे पीड़ित पीडब्लू 1 को अपने दाहिने कंधे और बाएं अंगूठे पर घर्षण की चोटें आईं जो प्रकृति में सरल हैं।

उत्तरदायी-राज्य/पुलिस की प्रस्तुतियाँ:

7. राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं का चाकू (प्रत्येक एक) से लैस होना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उनका इरादा मारने का था और यह केवल प्रोविडेंस के कारण था कि उनकी जान बचाई गई थी।

विश्लेषण, कारण और निष्कर्ष: 8. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 इस प्रकार है:

853

शिवमणि बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि, वेल्लोर टॉक पुलिस स्टेशन, वेल्लोर जिला [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 854 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

‘307. हत्या का प्रयास।—जो कोई भी इस तरह के इरादे या ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है, और ऐसी परिस्थितियों अंतर्गत कि, यदि वह उस कार्य से मृत्यु का कारण बनता है, तो वह हत्या का दोषी होगा, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ सकता है, और वह दंडनीय भी होगा; और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को

चोट पहुंचती है, तो अपराधी या तो आजीवन कारावास या ऐसी सजा के लिए उत्तरदायी होगा जो यहां पहले उल्लिखित है।

आजीवन कैदियों द्वारा प्रयास।—जब इस धारा के अंतर्गत समाप्त होने वाला कोई भी व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा के अंतर्गत होता है, तो उसे चोट लगने पर मौत की सजा दी जा सकती है।

दृष्टांत

(क) उसे मारने के इरादे से जेड पर गोली चलाना, ऐसी परिस्थितियों अंतर्गत कि यदि मृत्यु हो जाती है, तो ए हत्या का दोषी होगा। ए इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है।

(ख) ए, एक कोमल वर्ष के बच्चे की मृत्यु का कारण बनने के इरादे से, इसे एक रेगिस्तानी स्थान पर उजागर करता है। ए ने इस धारा की अवहेलना की है, हालांकि बच्चे की मृत्यु नहीं होती है।

(ग) ए, जेड की हत्या करने का इरादा रखता है, एक बंदूक खरीदता है और उसे लोड करता है। ए ने अभी तक गलती नहीं की है। उसने इस धारा में उल्लंघन किया है, और यदि इस तरह के उल्लंघन से वह जेड को घायल करता है, तो वह इस धारा के पहले पैराग्राफ के उत्तरार्ध भाग द्वारा प्रदान की गई सजा के लिए उत्तरदायी है।

(घ) ए, ज़हर द्वारा जेड की हत्या करने का इरादा रखता है, ज़हर खरीदता है और उसे भोजन के साथ मिलाता है जो ए के संरक्षण में रहता है; ए ने अभी तक इस खंड में अपराध नहीं किया है। ए भोजन को जेड की मेज पर रखता है या इसे जेड के नौकरों को जेड की मेज पर रखने के लिए वितरित करता है। ए ने इस खंड में ऑफ-एनस डेफिनेड किया है।'

9. मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम, (2005) 5 एस. सी. सी. 554 में न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक नहीं था कि मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाली शारीरिक चोट को दोषी ठहराया जाना चाहिए था। इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत केवल इस आधार पर गैर-दोषसिद्धि कि साधारण चोट लगी थी, निश्चित रूप से एक मामले के रूप में पालन नहीं करता है। उसी निर्णय में यह बताया गया था कि '। न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या

अधिनियम, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, इरादे या ज्ञान के साथ और धारा अंतर्गत उल्लिखित परिस्थितियों अंतर्गत किया गया था।' स्थिति यह है कि क्योंकि

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 को जग राम बनाम हरियाणा राज्य, (2015) 11 में दोहराया गया है।

एस. सी. सी. 366 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम कान्हा (2019) 3 एस. सी. सी. 605।
फिर भी,

जाग राम (ऊपर) और कान्हा (ऊपर), यह देखा गया कि जबकि गंभीर या जानलेवा चोट के अंतर्गत एक दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं था

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307, 'अभियुक्त के इरादे का पता वास्तविक चोट, यदि कोई हो, के साथ-साथ आसपास की परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। अन्य बातों के अलावा, उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति और हमले की गंभीरता को इरादे का अनुमान लगाने के लिए माना जा सकता है।' 1

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय आश्चर्य है कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। मान लीजिए, बार-बार या गंभीर प्रहारों का कोई आरोप नहीं है। यहां तक कि पीडब्लू¹ और पीडब्लू² पर चोटें भी सरल प्रकृति की पाई गई हैं, जो अपीलार्थियों के पक्ष में एक अतिरिक्त बिंदु है।

11. हम आगे अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि अभिलेख पर सामग्री से, केवल भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 323 2 और 324 3 के अंतर्गत खुलासा किया जा सकता है। इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है।

12. ऊपर की गई चर्चाओं की पृष्ठभूमि में और समग्र दृष्टिकोण लेने पर, आक्षेपित निर्णय केवल इस हद तक भिन्न है

1 कान्हा (ऊपर) का पैरा 13।

2 323.स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के लिए दंड।—जो कोई भी, धारा 334 द्वारा उपबंधित मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है, या एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।'

3 '324. खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुँचाना।—जो कोई भी, धारा 334 द्वारा उपबंधित मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से गोली चलाने, छुरा घोंपने या काटने के लिए किसी उपकरण के माध्यम से, या किसी ऐसे उपकरण के माध्यम से चोट पहुँचाता है जिससे मौत होने की संभावना है, या फिर किसी गर्म पदार्थ के माध्यम से, या किसी जहर या किसी संक्षारक पदार्थ के माध्यम से, या किसी विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से या किसी ऐसे पदार्थ के माध्यम से जो मानव शरीर के लिए सांस लेने, निगलने, या रक्त में प्राप्त करने के लिए हानिकारक है, या किसी भी जानवर के माध्यम से, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक हो सकता है, या फिर दोनों के साथ।

' 855

शिवमणि बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि, वेल्लोर टॉक पुलिस स्टेशन, वेल्लोर जिला
[अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 323 और 324 के अंतर्गत संशोधित किया गया है और लगाई गई सजा को भी पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम कर दिया गया है। लगाए गए शुल्क को बनाए रखा जाता है। अपीलार्थी अपने जमानत बांड की देनदारियों, यदि कोई हो, से मुक्त हो जाते हैं।

13. अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान